हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 04 अंक 41 | लखनऊ शनिवार 18 अक्टूबर 2025 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

संक्षिप्त समाचार

24 सितंबर की लेह हिंसा की जांच करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान : गृह मंत्रालय

नई दिल्ली(यूएनएस)।लेह में 24 सितंबर को भड़की हिंसा की जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान को नियुक्त किया है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उस दिन गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, और उस दौरान चार लोगों की मौत कैसे हुई।केंद्र सरकार ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की जांच के लिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज बी. एस. चौहान को नियुक्त किया है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उस दिन गंभीर कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, और उस दौरान चार लोगों की मौत कैसे हुई। सरकारी बयान के अनुसार 24 सितंबर को लेह शहर में गंभीर कानून.व्यवस्था की समस्या पैदा हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कार्रवाई हुई और चार लोग मारे गए। मंत्रालय ने कहाए श्निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने आज न्यायिक जांच की घोषणा की हैए जिसे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज डा.चौहान करेंगे। यह जांच उन परिस्थितियों की पड़ताल करेगी, जिनके कारण गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और चार व्यक्तियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई।सरकार ने यह भी कहा कि वह किसी भी समय संवाद के लिए तैयार है और आगे भी उच्च स्तरीय समिति या किसी अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से एपेक्स बॉडी लेह एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ बातचीत को स्वागत करती रहेगी। सरकार ने भरोसा जताया कि लगातार बातचीत से जल्दी ही सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे और वह लेह के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।जानकारी के अनुसार 24 सितंबर को सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने लेह के लिए राज्य बनने और छठे अनुसूची के तहत विशेष दर्जा देने की मांग की थी। इस हिंसा में चार लोग मारे गए और लगभग 90 लोग घायल हुए। दो दिन बाद पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत गिरफ्तार किया और उन्हें जोधपुर जेल भेज दिया, उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया।

ट्रांसजेंडरों से भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र को समान अवसर नीति बनाने के दिए निर्देश

नई दिल्ली(यूएनएस)।सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता जताई है। इसी के साथ केंद्र सरकार को समान अवसर नीति बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता जताई है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार के रवैये पर निशारा व्यक्त की।शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को समान अवसर नीति बनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में 2019 में कानून बनने के बावजूद ट्रांसजेंडरों के साथ हो रहे भेदभाव पर चिंता व्यक्त की। वहीं अदालत ने केंद्र को एक सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तीन महीने के भीतर श्समान अवसर नीति बनाने का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 अब निष्क्रिय हो गए हैं। पीठ ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि संबंधित नियमों को क्रूरतापूर्वक समाप्त कर दिया गया है और केंद्र और राज्यों ने उनके प्रति घोर उदासीन रवैया अपनाया है।पीठ ने कहा यह समुदाय भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने का सामना कर रहा है, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक अवसरों की कमी और गैर.समावेशी शैक्षिक नीतियों ने उनके संघर्षों को और बढ़ा दिया है।भेदभाव पर निराशा व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा कि 2014 में नालसा मामले में इस न्यायालय के फैसले के 10 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद, जिसके कारण संसद को 2019 में एक कानून बनाना पड़ा, ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए मुख्यतः उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लेना पड़ता है।रोजगार और पेशेवर क्षेत्रों में भेदभाव पर पीठ ने कहा कि 2019 के अधिनियम और 2020 के नियमों के लागू होने के बावजूद ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार और पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पीठ ने कहा तीसरे लिंग के विकल्प के अभाव जैसी व्यवस्थागत बाधाएं संगठित कार्यबल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रवेश को असंभव बना देती हैं। अगर उन्हें नौकरी पर भी रखा जाता है, तो उनसे अपनी पहचान छिपाने की अपेक्षा की जाती है, जो अनुच्छेद 21 के तहत किसी के सम्मान के अधिकार का घोर उल्लंघन है।शीर्ष अदालत ने एक ट्रांसजेंडर महिला द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया। वह नौकरी में अपने साथ हुए भेदभाव और अपमान से व्यथित थी, जिसके कारण कथित तौर पर उत्तर प्रदेश और गुजरात के दो निजी स्कूलों से उसकी पढ़ाई छूट गई थी।अदालत ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों और गुजरात के स्कूल को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उसके साथ हुए भेदभाव के लिए 50.50 हजार रुपए का भुगतान करें।

पिछले 11 वर्षों में चुनौतियों का सामना करते हुए भारत ने हर डर को दूर किया

सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक, अब कोई नहीं रोक सकता : पीएम मोदी

नई दिल्ली(यूएनएस)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की है। उन्होंने इस दौरान कहा कि पहले दुनिया सोचती थी कि इतनी सारी समस्याओं में उलझा भारत कभी इनसे उबर नहीं पाएगा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर डर को दूर किया है और हर चुनौती पर विजय पाई है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर चुप नहीं रहता, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देता है। उन्होंने कहा कि भारत अब रुकने के मूड में नहीं है और दुनिया में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आएं, देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री ने यह बातें नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं हैं।पीएम मोदी ने इस दौरान कहा भारत अब आतंकवादी हमलों पर चुप नहीं बैठता।सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि देश अब पहले जैसा नहीं रहा, अब हमला होने पर तुरंत कार्रवाई होती है और दुनिया भारत की क्षमता को देख रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जोर देकर कहा भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। हम न रुकेंगे, न थमेंगे। 140 करोड़ भारतीय पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं।उन्होंने कहा कि पहले दुनिया को लगता था कि भारत अपनी समस्याओं में उलझकर आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर डर और चुनौती को पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि एक समय भारत को कमजोर पांच अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता था। श्आज भारत दुनिया की प्रमुख पांच अर्थव्यवस्थाओं में है। चिप्स से लेकर शिप्स तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है।उन्होंने कहा कि आज का भारत किसी भी संकट के सामने घुटने नहीं टेकताए बल्कि चुनौती को अवसर में बदलता है।प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कोविड के उस दौर को याद कीजिए, जब दुनिया जीवन और मृत्यु के साये में जी रही थी। लोगों को लग रहा था कि भारत के कारण दुनिया डूब जाएगी।लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित कर दिया। हमने तेजी से अपनी वैक्सीन विकसित की। हमने रिकॉर्ड समय में टीके लगाए। इतने बड़े संकट पर काबू पाकर हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गए।उन्होंने कहा कि इसी आत्मविश्वास ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज दुनिया में कई स्पीड ब्रेकर और रोडब्लॉक हैं, लेकिन भारत की गति नहीं रुकेगी। जब दुनिया में युद्ध की खबरें सुर्खियां बन रही थीं, तब भी भारत आगे बढ़ता रहा। यह अनस्टॉपेबल इंडिया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि हर नागरिक इस यात्रा में अपनी भूमिका निभाए ताकि देश और ऊंचाइयों को छू सके। पीएम मोदी ने देश की उपलब्धियों और बदलावों पर कई अहम बातें भी कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैंकिंग सिस्टम को आम लोगों के लिए खोल दिया। श्हमने 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते मिशन मोड में खोले। आज हर गांव में किसी न किसी तरह बैंकिंग की सुविधा मौजूद है। डिजिटल लेन.देन ने भारत को दुनिया के सबसे वित्तीय रूप से शामिल देशों में शामिल कर दिया है।वहीं पेट्रोल पंप और गैस कनेक्शन पर पुरानी नीतियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा 2014 से पहले कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बचाने के लिए रात में पेट्रोल पंप बंद करने की तैयारी कर रही थी। उस दौर में गैस कनेक्शन पाने के लिए सांसद से सिफारिशी पत्र लेना पड़ता था। हमने सत्ता में आते ही 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए।प्रधानमंत्री ने बताया कि ई.संजीवनी एप के जरिए देशभर में लोग अपने मोबाइल से डॉक्टरों से जुड़ सकते हैं। अब तक 42 करोड़ लोगों को इस सेवा से इलाज की सुविधा मिली है। आज ही एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। यह सिर्फ सुविधा नहीं है, संकट के समय तुरंत मदद की गारंटी है। उन्होंने कहा जब सरकार लोगों पर जोर नहीं डालती, तभी लोग अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ते हैं। जितना ज्यादा सरकारी नियंत्रण होगा, उतनी रफ्तार धीमी होगी। जितना ज्यादा लोकतंत्र होगा, विकास उतनी ही तेजी से होगा। कांग्रेस ने 60 साल तक नीतियों को सरकारी नियंत्रण में रखा। हमने इस सोच को बदला।इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की तरक्की अब दुनिया में नए अवसर बना रही है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर अपने सबसे बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए। यह दिखाता है कि दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। आज भारत वैश्विक सप्लाई चेन का अहम केंद्र बन रहा है।उन्होंने कहा आयकर और जीएसटी में बड़े सुधारों से ईमानदार करदाताओं को फायदा हुआ है। बिक्री के रिकॉर्ड टूट रहे हैं।

21वीं किस्त, दिवाली से पहले किसानों के खाते में आ सकते हैं 2000 रुपये

नई दिल्ली(यूएनएस)। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को एक बार फिर राहत की उम्मीद है। केंद्र सरकार जल्द ही इस योजना की 21वीं किस्त जारी करने की तैयारी में है। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में यानी हर चार महीने में 2000 रुपये के रूप में मिलती हैं।मौजूदा जानकारी के अनुसार अब तक देशभर के करोड़ों किसानों को 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है, और 21वीं किस्त अक्टूबर के अंत या दिवाली से पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से किस्त जारी करने की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, ताकि किसानों को खेती से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए सीधी वित्तीय सहायता दी जा सके। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है।अगर कोई किसान यह जानना चाहता है कि उसका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो वह पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकता है।वेबसाइट पर सेक्शन में जाकर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर डालने पर यह जानकारी मिल जाएगी कि किसान को पिछली किस्तें मिली हैं या नहीं और अगली किस्त का स्टेटस क्या है।

ऐसा करने को मजबूर किया गया

टैरिफलगाकर अब पछता रहे ट्रंप, बोले चीन पर 100: शुल्क टिकाऊ नहीं

वाशिंगटन(यूएनएस)।चीन पर 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये टिकाऊ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि चीन पर लगाया गया 100 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ टिकाऊ नहीं हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है, जब उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक होने जा रही है। दरअसल फॉक्स बिजनेस के साथ एक इंटरव्यू में जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या इस साल की शुरुआत में दोनों देशों ने एक.दूसरे पर जो टैरिफ लगाए थे, वे बने रह सकते हैं।इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि चीन पर लगा 100 फीसदी टैरिफ टिकाऊ नहीं है। इसी के साथ ट्रंप ने आगे कहा कि बीजिंग ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया।इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने चीन पर लंबे समय से चली आ रही अनुचित प्रथाओं का आरोप लगाया।

भगोड़े मेहुल चोकसी को बड़ा झटका, कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, आदेश के खिलाफ करेगा अपील

नई दिल्ली(यूएनएस)।भगोड़े हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। एंटवर्प कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी।पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बड़ा झटका लगा है। एंटवर्प कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने कहा कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों की ओर से उसकी गिरफ्तारी वैध थी।एंटवर्प की एक अदालत ने शुक्रवार 17 अक्तूबर को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने बताया कि यह आदेश भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के मामले को पुख्ता मान्यता प्रदान करता है, क्योंकि चोकसी के पास बेल्जियम की एक उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है।एंटवर्प की कोर्ट ने साफ कहा कि भारतीय एजेंसियों की मांग वैध है और बेल्जियम पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी कानूनी रूप से वैध थी। कोर्ट के फैसले के साथ भारत की एजेंसियां सीबीआई और ईडी को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है।हालांकि चोकसी के वकीलों ने कोर्ट में कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। इसलिए फिलहाल चौकसी को तुरंत भारत नहीं भेजा जाएगा।एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा आदेश हमारे पक्ष में आया है।

सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया विभागों का बंटवारा, खुद संभाले महत्त्वपूर्ण विभाग

गांधीनगर(यूएनएस)।गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हुए कैबिनेट फेरबदल के बाद अब मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई अहम विभागों को खुद के पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम हर्ष संघवी को गृह विभाग समेत कई जिम्मेदारियां मिली है।गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने कैबिनेट में विभागों का नया बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण समेत कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है। वहीं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को गृह विभाग, पुलिस, आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, शराब और उत्पाद शुल्क, परिवहन, कानून और न्याय, खेल और युवा सेवाओं जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। उनके पास सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े कई अहम जिम्मेदारियां हैं।वहीं कैबिनेट मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त विभाग, शहरी विकास और शहरी आवास की जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग राज्य की आर्थिक और शहरी योजनाओं के लिए अहम माना जाता है। जबकि मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल को ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स, पंचायत और ग्रामीण आवास, विधान और संसदीय कार्य विभाग सौंपे गए हैं।

जंगलराज की वापसी का प्रतीक है लालू.राहुल की जोड़ी, 14 नवंबर मनायेंगे बड़ी दिवाली : अमित शाह

सारण-बिहार(यूएनएस)।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार को फिर से अंधकार में नहीं जाने देना है। क्योंकि, राज्य में विकास की जो रफ्तार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार ने दी है, उसे बरकरार रखने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जनता एक बार फिर से एनडीए को भारी बहुमत से जिताए।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सारण के तरैया विधानसभा में एनडीए गठबंधन की ओर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सूबे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी। बिहार की जनता ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि बिहार की जनता को इस बार घ्चार. चार दीपावली मनाने का अवसर मिल रहा है। 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी, तब वह दिन बिहार की एक बड़ी दीपावली होगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज सारण जिले के तरैया प्रखंड अंतर्गत मंझोपुर गांव में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए समर्थन मांगा है। अमित शाह ने एनडीए के अंदर नेतृत्व को लेकर चल रहे सवालों को समाप्त करने की कोशिश की है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष खास कर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी को जंगलराज की वापसी का प्रतीक है। क्योंकि यह दोनों नेता बिहार को फिर से अराजकता की ओर धकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी, तब बिहार में अपहरण, हत्या और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन एनडीए की सरकार ने विकास, कानून व्यवस्था और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को जाति और भावनाओं के जाल में नहीं फंसना हैं। बल्कि विकास और सुशासन को ध्यान में रखकर मतदान करने की जरूरत है। सभा के अंत में उन्होंने एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल सीट जीतने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। उन्होंने भरोसा जताया कि सारण की सभी सीटों पर एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य फिर से विकास की राह पर अग्रसर होगा।

कार्यक्रम **विद्यार्थियों को पढ़ाई.लिखाई के लिए प्रत्येक स्तर पर मेहनत करनी चाहिए : मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री ने 10,28,205 छात्र.छात्राओं के खातों में 297.95 करोड़ की छात्रवृत्ति हस्तांतरित की

लखनऊ . संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर जी ने कहा था कि पढ़-लिख कर ही हम स्वावलम्बन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर देश व समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई.लिखाई के लिए प्रत्येक स्तर पर मेहनत करनी चाहिए। बाबा साहब ने सीमित संसाधनों के बावजूद उच्च शिक्षा अर्जित की। वर्तमान में संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि हमें अपने स्तर पर थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री आज यहां दशमोत्तर एवं पूर्वदशम् छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,28,205 छात्र.छात्राओं के खातों में 297.95 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।इस अवसर पर उन्होंने छात्र.छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण.पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्र.छात्राओं से संवाद किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना होगा। संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पुस्तकालय जाने की आदत डालनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा। आपके मन में इनोवेशन और सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ऐसा कर आप समाज में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने योग्य बन सकते हैं। युवाओं में असीम ऊर्जा व प्रतिभा है। इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ वह स्वयं के साथ.साथ अपने परिवार, समाज व देश को उपलब्ध करा सकते हैं। यही स्कॉलरशिप प्रदान करने का उद्देश्य है। विगत साढ़े 08 वर्षों में 04 करोड़ 27 लाख से अधिक छात्र.छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा का लाभ प्रदान किया गया।दीपावली पर्व से ठीक पूर्व आज 10 लाख 28 हजार 205 से अधिक छात्र.छात्राओं को लगभग 300 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति का लाभ डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। विजयादशमी पर्व से ठीक पूर्व भी बड़ी संख्या में छात्र.छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की गयी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार करते हुए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रत्येक छात्र.छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरित करने की प्रणाली प्रदेश में लागू की गयी। विद्यार्थियों को वर्ष के अन्त में स्कॉलरशिप प्रदान करने के स्थान पर वर्ष में दो बार अक्टूबर व जनवरी महीने में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016.17 तक प्रदेश के 46 लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे।

नया समय तत्काल प्रभाव से लागू

बदल गया अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का समय, भारत.पाक सीमा पर बंद रहेंगे गेट

अमृतसर-पंजाब(यूएनएस)। वाघा.अटारी बॉर्डर पर रोजाना होने वाली रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। सर्दियां शुरू होने की वजह से टाइमिंग में बदलाव किया गया है। भारत.पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा अटारी पर होने वाला रिट्रीट समारोह अब सर्दियों के चलते आधा घंटा पहले शुरू होगा। यह फैसला सीमित दिन के उजाले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीएसएफ के प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण महल ने बताया कि अब यह समारोह शाम 5 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा।पहले इसका समय शाम 5.30 बजे से 6 बजे तक था।नया समय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते अब भारत.पाक सीमा गेट बंद रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच कोई पारंपरिक अभिवादन या रस्में नहीं होंगी। बीएसएफ ने 24 अप्रैल से इन पारंपरिक रस्मों को स्थगित कर दिया था। अटारी, हुसैनीवाला और सादकी बॉर्डर पर रोजाना ध्वज अवतरण समारोह जारी है, चाहे पाकिस्तानी पक्ष शामिल हो या नहीं।उल्लेखनीय है कि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीटिंग रिट्रीट सीमा समारोह कहा जाता है।

संपादकीय

भारत एआई का गढ़

भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का गढ़ बनने जा रहा है। यही आकलन करने के बाद गूगल ने आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई का डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह डाटा केंद्र, अमरीका से बाहर, सबसे बड़ा केंद्र होगा। गूगल ने आगामी पांच सालों में 15 अरब डॉलर खर्च करने का ऐलान राजधानी दिल्ली में आयोजित एक मेगा इवेंट में किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आदि इस मेगा आयोजन में उपस्थित रहे। गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कूरियन ने खुलासा किया कि आज 14, 000 से अधिक भारतीय गूगल के साथ जुड़े हैं और गूगल की 5 एआई लैब्स पहले से ही भारत में सक्रिय हैं। विशाखापट्टनम का केंद्र गूगल के संपूर्ण एआई सिस्टम का हिस्सा होगा, जो भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सॉल्यूशंस और एआई मॉडल्स को तेजी से स्केल करेगा। गूगल के थॉमस ने यह स्पष्ट घोषणा की कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि एआई नवाचार का जेनरेटर बन रहा है। ह्न भारत में अदाणी समूह के साथ मिल कर यह एआई केंद्र बनाया जाएगा। गूगल का इतना बड़ा निर्णय भारतीय बाजार और भारत में एआई को ग्रहण करने की संभावनाओं की ताकत को सत्यापित करता है। भारत सरकार ने एआई मिशन के लिए 5 साल के दौरान 10, 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। उसके तहत 38, 000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) लगाई गई हैं। प्रौद्योगिकी और एआई पारिस्थितिकी तंत्र में करीब 60 लाख लोग कार्यरत हैं। इस साल प्रौद्योगिकी क्षेत्र का राजस्व 280 अरब डॉलर को पार कर सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में 2035 तक एआई 1.7 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकता है। अंतरराष्ट्रीय डाटा कॉरपोरेशन के मुताबिक, भारत का एआई बाजार 2025 में करीब 8 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल भारत विश्व में सबसे बड़ा ऐसा देश और समाज है, जो अभी से एआई के साथ परिवर्तन लाने को उत्साहित है। विशाखापट्टनम को इसलिए चुना गया है, क्योंकि आंध्रप्रदेश की राजधानी रहते हुए हैदराबाद को ह्यसाइबर सिटीह्ल का विशेषण मिला था। तेलंगाना के गठन के बाद समीकरण बदले। अब हैदराबाद उसकी राजधानी है, लिहाजा आंध्र के विशाखापट्टनम को गूगल की विराट परियोजना के लिए चुना गया। यहां गूगल के विकास और बढ़ोतरी की अपार क्षमताएं हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर यह क्षेत्र एआई की रीढ़ है।

चिंतन-मनन

भक्त के भीतर रहते हैं कृष्ण

जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे।

तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली और विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी-कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले-भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े-बड़े विद्वान पुरुष हैं, जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं।अतः कृष्णभावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञानरहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे।

आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है- जो लोग शुद्धभक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। भगवान अजरुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षो तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे।परम सत्य, कृष्ण, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं।शुद्धभक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है।

पराली जलाने की आग में झुलसता उत्तर भारत

डॉ. प्रियंका सौरभ

हर वर्ष जब धान की कटाई का मौसम आता है, तब पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठने वाला धुआँ आसमान को धुंध से भर देता है। यह केवल खेतों की आग नहीं होती, बल्कि भारत की कृषि नीति, आर्थिक असमानता और पर्यावरणीय असंतुलन की जलती हुई तस्वीर होती है। दिल्ली तथा उसके आस-पास के क्षेत्र इस धुएँ से ढक जाते हैं और वायु गुणवत्ता अत्यंत गंभीर स्तर तक पहुँच जाती है। कानूनी रूप से पराली जलाना प्रतिबंधित है, फिर भी किसान इसे हर साल दोहराते हैं क्योंकि इसके पीछे अनेक सामाजिक और आर्थिक कारण जुड़े हैं।

पराली जलाने का मूल कारण खेतों में बचा हुआ धान का ठूँठ होता है। जब धान की फसल कट जाती है, तब खेत में रह गए अवशेष को हटाने के लिए किसानों के पास न समय होता है न साधन। पंजाब और हरियाणा की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से धान और गेहूँ पर आधारित है। सन् 1960 के दशक की हरित क्रांति ने इन राज्यों को देश का अन्न भंडार तो बना दिया, परंतु कृषि को एकरूपी और जल-प्रधान भी बना दिया। भूजल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए सन् 2009 में पंजाब में 'उप-जल संरक्षण अधिनियम' लागू किया गया, जिसके अंतर्गत धान की रोपाई जून के अंत तक करने का निर्देश दिया गया ताकि मानसूनी वर्षा का लाभ लिया जा सके। परिणामस्वरूप धान कटाई और गेहूँ की बुवाई के बीच केवल दस से बीस दिन का अंतर रह गया। इतने कम समय में किसान पराली को एकत्रित या सड़ाकर खेत तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वे सबसे तेज और सस्ता उपाय-जलाना-चुन लेते हैं।

दूसरा बड़ा कारण आर्थिक है। पराली हटाने या निपटाने के लिए जो मशीनें चाहिए-जैसे सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर, बेलर या रोटावेटर-वे अत्यंत महँगी हैं। छोटे और सीमांत किसान जिनकी जोत तीन हेक्टेयर से भी कम है, वे इन मशीनों को खरीदने या किराए पर लेने में असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए, हैप्पी सीडर का किराया लगभग दो से तीन हजार रुपये प्रति एकड़ पड़ता है, जबकि पराली जलाने में केवल माचिस और थोड़े डीजल का खर्च आता है। यही व्यावहारिकता इस समस्या को गहराई तक जकड़े हुए है।

तीसरा कारण पराली का कम उपयोग मूल्य है। पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली अधिकतर धान की किस्में साधारण होती हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ऐसी पराली पशु चारे के रूप में प्रयोग योग्य नहीं होती और न ही इससे जैव ईंधन या खाद आसानी से बनाई जा सकती है। पूर्वी भारत के राज्यों में धान की पराली पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में आती है, परंतु पंजाब-हरियाणा में यह उपयोग सीमित है। इसीलिए यहाँ पराली किसानों के लिए किसी आर्थिक लाभ का साधन नहीं बन पाती।

चौथा कारण है श्रम की कमी और जोत का विखंडन। प्रवासी मजदूरों की संख्या घट रही है, और छोटे खेतों में मशीनरी लगाने की क्षमता नहीं है। समय की कमी और श्रमिकों के अभाव में किसान अगली फसल बोने की जल्दी में पराली को जला देते हैं।

सामाजिक दृष्टि से भी पराली जलाना वर्षों से एक स्वीकृत प्रक्रिया बन चुकी है। किसानों को यह लगता है कि खेत की सफाई का यही सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है। कानूनों और जुमार्नों के बावजूद यह प्रथा इसलिए जारी है क्योंकि प्रवर्तन ढीला है और राजनीतिक दबावों के कारण प्रशासन कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता। वर्ष 2023 में पंजाब में लगभग साठ हजार पराली जलाने की घटनाएँ दर्ज की गईं, जबकि जुमार्ना और निगरानी दोनों व्यवस्था में थे।

अब प्रश्न यह है कि इस समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है?

स्पष्ट है कि केवल प्रतिबंध या दंड इस समस्या को समाप्त नहीं कर सकते। आवश्यक है कि ऐसी रणनीति अपनाई जाए जो किसान की आजीविका और पर्यावरण संरक्षण दोनों को साथ लेकर चले।

पहला समाधान है फसल विविधीकरण। पंजाब और हरियाणा की भूमि लगातार धान-गेहूँ चक्र से थक चुकी है। जल स्तर भी नीचे जा रहा है। अतः मक्का, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन फसलों के लिए यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा सुरक्षा और निश्चित खरीद सुनिश्चित करे तो किसान धीरे-धीरे धान पर निर्भरता कम कर सकते हैं। हरियाणा की 'भावांतर भरपाई योजना' इस दिशा में एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें किसानों को मूल्य अंतर की भरपाई दी जाती है।

दूसरा समाधान है यंत्रीकरण और साझा संसाधन। किसानों को मशीनें साझा उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जाएँ। पंचायत या सहकारी समितियों के स्तर पर 'कस्टम हायरिंग केंद्र' स्थापित हों, जहाँ से किसान कम किराए पर हैप्पी सीडर या सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली जैसी मशीनें ले सकें। केंद्र सरकार की 'फसल अवशेष प्रबंधन योजना' के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा में एक लाख से अधिक मशीनें बाँटी गई हैं, पर इनकी पहुँच सभी किसानों तक नहीं हो पाई है। यदि हर गाँव में सामुदायिक यांत्रिक केंद्र बने, तो किसान पराली जलाने से बचेंगे।

तीसरा उपाय है पराली का औद्योगिक उपयोग। पराली को कचरा न मानकर एक संसाधन के रूप में देखा जाए। इससे जैव ऊर्जा, एथेनॉल, कागज, पैकेजिंग और निर्माण सामग्री तैयार की जा सकती है। उदाहरण के लिए, भारतीय तेल निगम की पानीपत जैव रिफाइनरी प्रतिवर्ष लगभग दो लाख टन पराली से एथेनॉल बनाती है। यदि इस प्रकार की परियोजनाएँ हर जिले में स्थापित हों तो पराली किसानों के लिए आय का स्रोत बनेगी और जलाने की आवश्यकता कम होगी। सरकार को परिवहन सहायता, खरीद अनुबंध और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की नीति बनानी चाहिए।

चौथा कदम होना चाहिए कृषि-पर्यावरणीय समय निर्धारण। धान की छोटी अवधि वाली किस्में जैसे पी.आर.-126 या डी.आर.आर. धान-44 अपनाने से किसानों को फसल कटाई और बुवाई के बीच कुछ अतिरिक्त दिन मिल सकते हैं। इस समय का उपयोग पराली प्रबंधन में किया जा सकता है। इसके साथ-साथ परिशुद्ध कृषि यानी सटीक तकनीकी साधनों का प्रयोग, जल-सिंचाई प्रणाली में सुधार और जैविक खाद उपयोग से भी पर्यावरणीय लाभ मिलेगा।

पाँचवाँ, सामुदायिक प्रोत्साहन और जनजागरूकता। पराली न जलाने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाए, गाँव स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित हो और 'शून्य दहन ग्राम' घोषित किए जाएँ। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में 'पुसा डीकंपोजर' नामक जैविक घोल के प्रयोग से पराली को खेत में ही खाद में बदला जा रहा है। यदि इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो पराली जलाने की आवश्यकता नहीं बचेगी।

छठा, प्रशासनिक तालमेल और नीति-समन्वय। केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच सामंजस्य होना चाहिए ताकि कृषि, पर्यावरण और ऊर्जा विभाग एक साझा योजना के अंतर्गत काम करें। पराली प्रबंधन को ग्रामीण रोजगार योजना, जैव ऊर्जा मिशन और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मनरेगा के अंतर्गत पराली एकत्रीकरण या जैव खाद इकाइयों में कार्य को रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

सातवाँ, शहरी-ग्रामीण सहभागिता भी इस दिशा में उपयोगी होगी। दिल्ली जैसे महानगर जहाँ प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, उन्हें अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निधि के माध्यम से पंजाब-हरियाणा के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे प्रदूषण के स्रोत और पीड़ित क्षेत्र के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित होगी। इसके साथ-साथ तकनीकी निगरानी प्रणाली को भी सशक्त बनाना चाहिए।

महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के बाद बिहार- राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं?

संतोष कुमार पाठक

2024 के लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों की मदद से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उस यूपीए के नाम को भी त्याग दिया जिसके बैनर तले कांग्रेस ने वर्ष 2004 से 2014 तक देश में राज किया था। लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए की जगह पर राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाया जिसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया।

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सहयोगी दलों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री तो बन गए लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार विपक्षी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें दिलाने का श्रेय लेकर कांग्रेस ने राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ हद तक कांग्रेस को अपने इस अभियान में कामयाबी मिलती भी दिखाई दी। वोट चोरी का अभियान चला कर और बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल कर राहुल गांधी अपने आपको विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करने में थोड़े बहुत कामयाब होते भी दिखाई दिए।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव से लेकर तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं डीएमके सुप्रीमो स्टालिन तक से उनके व्यक्तिगत संबंध मजबूत होते नजर आए। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव जीतने में राहुल गांधी और नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की व्यक्तिगत केमिस्ट्री का जबरदस्त योगदान माना जाता है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो खुलकर राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार तक बता दिया।

लेकिन इन सबके बावजूद अचानक देश की राजनीति तेजी से बदलती हुई नजर आने लगी है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीट और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस आमने-सामने आ गए है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसदों के लिए होने वाले चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने तीनों सेफ सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस को जो चौथी सीट ऑफर की है, उसे जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस पहले से ही इसे लेकर अपने सहयोगी दल से नाराज चल रही है वहीं अब विधानसभा की जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर भी मामला फंसता हुआ ही नजर आ रहा है। राज्य में विधानसभा की 2 सीटों- बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला की पार्टी पर गठबंधन के सिद्धांतों का अनादर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वह राज्यसभा की एक सेफ सीट देने के अपने वादे से मुकर गई। कांग्रेस ने गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए सख्त शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो नेशनल कांफ्रेंस उन्हें विधानसभा की एक सीट दे या फिर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी।

महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के समय से ही शुरू हुई खटास कम होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया भर में भेजे गए सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर एनसीपी और कांग्रेस के सुर अलग-अलग तो नजर आए ही। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद इस्तीफे की बाध्यता वाले बिल पर गठित की जाने वाली जेपीसी में शामिल नहीं होने को लेकर भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों को अपने साथ ला पाने में नाकामयाब होती नजर आ रही है।

वहीं बिहार का मामला तो राहुल गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता को लेकर सबसे बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी है जिसके नेता तेजस्वी यादव ने खुल कर राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का समर्थन कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो लगातार पूछे जाने के बावजूद भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रहे हैं। जबकि राजनीतिक सच्चाई तो यही है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस और आरजेडी में सीटों के बंटवारे को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सहयोगी दलों के साथ कांग्रेस की यह खींचतान और महत्वपूर्ण मौकों पर राहुल गांधी की गैरमौजूदगी उनके नेतृत्व पर ही सवालिया निशान लगाती नजर आती है। पता नहीं राहुल गांधी इस तथ्य को समझ पा रहे हैं या नहीं और इससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिर राहुल गांधी को इस तरह की सलाह कौन देता है कि उन्हें दिल्ली में होने के बावजूद तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। केसी वेणुगोपाल और तेजस्वी यादव की जगह पर अगर राहुल सीधे तेजस्वी के साथ बैठकर बात करते तो शायद मामला इतना उलझता नहीं।

गरीबी है मानवता के भाल पर बड़ा कलंक

ललित गर्ग

आज दुनिया में लगभग सत्तर करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक अत्यंत गरीबी का अंत किया जाए, परंतु यह लक्ष्य अभी भी दूर प्रतीत होता है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, असमान आर्थिक नीतियाँ, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी ने गरीबी को नया रूप दिया है। अब गरीबी केवल रोटी की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की असमानता और सामाजिक अन्याय का भी प्रतीक बन चुकी है।

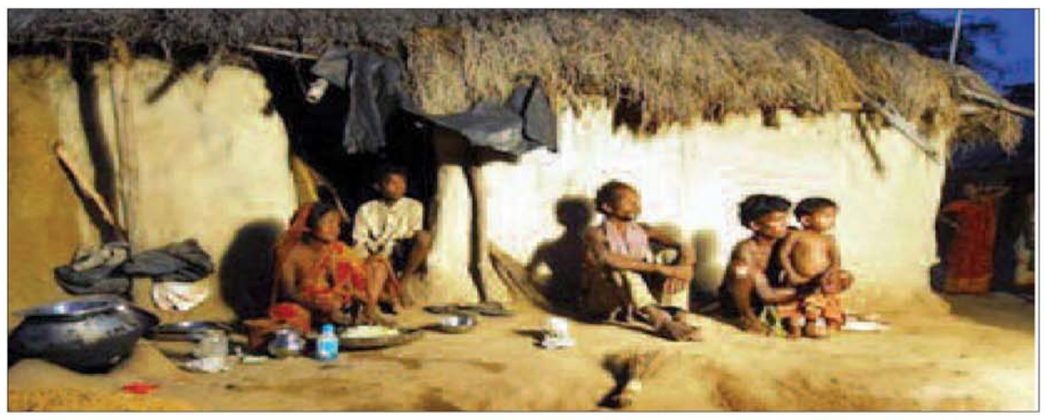

विश्व समुदाय हर वर्ष 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि मानवता के समक्ष खड़ी सबसे बड़ी चुनौती पर मंथन का अवसर है। सभ्यता के विकास, तकनीकी प्रगति, आर्थिक विस्तार और वैश्विक व्यापार के बावजूद आज भी करोड़ों लोग रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। गरीबी एक आर्थिक स्थिति मात्र नहीं है, यह मनुष्य की गरिमा पर सबसे बड़ा आघात है-यह उसके सपनों, आत्मविश्वास और अस्तित्व को कुचलने वाला सामाजिक अभिशाप है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1992 में गरीबी को खत्म करने के प्रयासों और संवाद को बढ़ावा देने के लिए इस दिन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य गरीबी में जी रहे लोगों के संघर्ष को स्वीकार करना और गरीबी के विभिन्न आयामों, जैसे कि आय की कमी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच की कमी आदि को संबोधित करना है। 2025 की थीम 'परिवारों के लिए सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित करके सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना' है। इस दिवस का उद्देश्य गरीबी और इसके कारणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, तथा गरीबी से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को उजागर करना है।

आज दुनिया में लगभग सत्तर करोड़ लोग अत्यंत गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि 2030 तक अत्यंत गरीबी का अंत किया जाए, परंतु यह लक्ष्य अभी भी दूर प्रतीत होता है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन, असमान आर्थिक नीतियाँ, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी ने गरीबी को नया रूप दिया है। अब गरीबी केवल रोटी की कमी नहीं, बल्कि अवसरों की असमानता और सामाजिक अन्याय का भी प्रतीक बन चुकी है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन कहते हैं-'गरीबी केवल आय का प्रश्न नहीं है, यह स्वतंत्रता की कमी है।' अर्थात जब किसी व्यक्ति के पास अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के अवसर नहीं होते, तभी वास्तविक गरीबी जन्म लेती है। भारत ने पिछले कुछ दशकों में गरीबी घटाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नीति आयोग के अनुसार, 2013-14 में जहाँ देश की 29 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में थी, वहीं 2019-21 तक यह घटकर लगभग 11 प्रतिशत रह गई। परंतु यह सफलता पूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि गरीबी का असर ग्रामीण इलाकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर अभी भी अधिक है। गरीबी का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है-जहाँ गरीब बच्चे स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं, वहीं परिवार बीमारी का खर्च नहीं उठा पाते। यह चक्र दर चक्र उन्हें फिर गरीबी में धकेल देता है। आजादी के अमृत काल में सशक्त भारत एवं विकसित भारत को निर्मित करते हुए गरीबमुक्त भारत के संकल्प को भी आकार देना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार ने वर्ष 2047 के आजादी के शताब्दी समारोह के लिये जो योजनाएं एवं लक्ष्य तय किये हैं, उनमें गरीबी उन्मूलन के लिये भी व्यापक योजनाएं बनायी गयी है। विगत ग्यारह वर्ष एवं मोदी के तीसरे कार्यकाल में ऐसी गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया गया है, जिससे भारत के भाल पर लगे गरीबी के शर्म के कलंक को धोने के सार्थक प्रयत्न हुए है एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों को ऊपर उठाया गया है। वर्ष 2005 से 2020 तक देश में करीब 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं तब भी भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जहां गरीबी सर्वाधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी उन्मूलन के लिये उल्लेखनीय एवं सफलतम उपक्रम किये हैं, उन्होंने गरीबी को राष्ट्र निर्माण की केंद्र बिंदु नीति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके नेतृत्व में सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई को केवल कल्याण योजनाओं तक सीमित न रखकर आत्मनिर्भरता के आंदोलन में बदल दिया। जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी ने गरीबों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों के सिर पर छत का सपना साकार किया और अब तक चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्त जीवन दिया और यह योजना केवल गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि समानता और सम्मान का प्रतीक बनी। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी के कठिन दौर में गरीबों को सुरक्षा कवच दिया, वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान ने गरीबी उन्मूलन का दीर्घकालिक रास्ता रोजगार, कौशल और स्वाभिमान के माध्यम से खोला। प्रधानमंत्री का यह कथन इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है-'गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार नहीं, समाज को भी संवेदनशील बनना होगा। जब हर गरीब का सपना हमारा सपना बनेगा, तभी समृद्ध भारत बनेगा।'

गरीबी केवल सरकारी योजनाओं से नहीं मिटेगी; इसके लिए एक व्यापक मानव-केंद्रित सोच की आवश्यकता है। शिक्षा को अधिकार नहीं, अवसर बनाना होगा, हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिलना चाहिए। समान आर्थिक अवसरों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि शहरी और ग्रामीण भारत के बीच की खाई घटे। पूंजी का उद्देश्य केवल मुनाफा नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण भी होना चाहिए। साथ ही, महात्मा गांधी के शब्दों में, 'गरीबी सबसे बड़ी हिंसा है'-यह भावना हमारे सामाजिक चरित्र में उतरनी चाहिए। जब तक समाज करुणा और साझेदारी की भावना नहीं अपनाएगा, तब तक गरीबी का अंत संभव नहीं। भारत आज गरीबी उन्मूलन का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत कर रहा है-जहाँ विकास का अर्थ केवल जीडीपी नहीं, बल्कि गरीब का उत्थान है। यह संदेश दुनिया के लिए भी प्रेरणा है कि यदि सबसे बड़ा लोकतंत्र करोड़ों लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकता है, गरीब मुक्त भारत के सपने को आकार दे सकता है तो वैश्विक समुदाय भी एकजुट होकर यह कर सकता है। गरीबी केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, यह मानवता की परीक्षा है। जब तक दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति भूखा सोएगा, तब तक सभ्यता का विकास अधूरा रहेगा। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि 'सच्ची प्रगति वही है, जिसमें समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो।' आज आवश्यकता है एक वैश्विक संकल्प की-'गरीबी नहीं, समानता हमारा धर्म बने।' जब हर राष्ट्र, हर समाज और हर व्यक्ति इस दिशा में जिम्मेदारी निभाएगा, तभी वह दिन आएगा जब गरीबी इतिहास का विषय होगी, वर्तमान का नहीं।

गरीबी व्यक्ति को बेहतर जीवन जीने में अक्षम बनाता है। गरीबी के कारण व्यक्ति को जीवन में शक्तिहीनता और आजादी की कमी महसूस होती है। गरीबी उस स्थिति की तरह है, जो व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने में अक्षम बनानी है। गरीबी ऐसी त्रासदी एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है जिसका कोई भी अनुभव नहीं करना चाहता। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि गरीबी कोई दैवीय अभिशाप नहीं है बल्कि यह मानवजाति द्वारा रचित सबसे बड़ी समस्या है। भारत में गरीबी का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर-गरीब में ऊंच-नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी आदि हैं। एक आजाद मुल्क में, एक शोषणविहीन समाज में, एक समतावादी दृष्टिकोण में और एक कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था में गरीबी रेखा नहीं होनी चाहिए। यह रेखा उन कर्णधारों के लिए शर्म की रेखा है, जिसको देखकर उन्हें शर्म आनी चाहिए। यहां प्रश्न है कि जो रोटी नहीं दे सके वह सरकार कैसी? जो अभय नहीं बना सके, वह व्यवस्था कैसी? जो इज्जत व स्नेह नहीं दे सके, वह समाज कैसा? जो शिष्य को अच्छे-बुरे का भेद न बता सके, वह गुरु कैसा?

गांधी, विनोबा एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबके उदय एवं गरीबी उन्मूलन के लिए 'अन्त्योदय' एवं 'सर्वोदय' की बात की। लेकिन राजनीतिज्ञों ने उसे निज्योदय बना दिया। जे. पी. ने जाति धर्म से राजनीति को बाहर निकालने के लिए 'संपूर्ण क्रांति' का नारा दिया। जो उनको दी गई श्रद्धांजलि के साथ ही समाप्त हो गया। 'गरीबी हटाओ' में गरीब हट गए। स्थिति ने बल्कि नया मोड़ लिया है कि जो गरीबी के नारे को जितना भुना सकते हैं, वे सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। कैसे समतामूलक एवं संतुलित समाज का सुनहरा स्वप्न साकार होगा? कैसे मोदीजी का नया भारत निर्मित होगा?

गुमशुदा की तलाश

क्या आपने इन्हें कही देखा है

रानी गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता

निवासी ग्राम सोरसा पोस्ट नवाबगंज तहसील हसनगंज थाना अजगैन जिला उन्नाव 209859 उत्तर प्रदेश

उम्र: 45 वर्ष

रंग: गोरा

लम्बाई:4-5 फ़ीट लगभग

Size: Slim

लापता 4/10/2025

किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर दिये गए नम्बरों पर सम्पर्क करें जानकारी देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा

राजेश:9170952262,अनिल:8175015702,अजीत:8417085017

जनता का सच, 9569036324

फुलवरिया गाँव में धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या, पुलिस जांच में जुटी

स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर

नानपारा। थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के फुलवरिया गाँव में शुक्रवार दोपहर एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, सहबूब अली उर्फ छोटकऊ (50 वर्ष) पुत्र शाह मोहम्मद निवासी फुलवरिया, शुक्रवार को बाजार से अपने गाँव लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर पीछे से धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि सहबूब अली की मौके पर ही मौत हो गई।

सूचना मिलते ही थाना नानपारा पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार, सहबूब अली कुछ समय पहले ही जेल से छूटे थे। वर्ष 2005 में उन्होंने अपने खालाजात भाई इंसान अली की हत्या की थी, जिसके मामले में उन्हें न्यायालय से सजा भी हो चुकी थी। सजा पूरी करने के बाद वह कुछ समय से गाँव में रह रहे थे।

घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पुलिस घटना के सभी पहलुओं की गहन जाँच कर रही है। मृतक के परिजनों से अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।"

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में थाना खैरीघाट पुलिस टीम द्वारा 06 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार थाना खैरीघाट जनपद बहराइच

ब्यूरो अब्दुल नासिर

बहराइच। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा चलाये जा रहे अभियान वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु दिये गये कड़े दिशा निर्देश के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी महसी श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थानाध्यक्ष थाना खैरीघाट श्री राशिद अली खान के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 18.10.2025 को भिन्न भिन्न अ0सं0 से सम्बन्धित 06 नफर वारण्टी को थाना खैरीघाट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों ६ निर्देशों का पालन करते हुये गिरफ्तार शुदा वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया। गिरफ्तारी की सूचना वारण्टी के परिजनों को जरिये उचित माध्यम से दी गयी।वारण्टी का नाम व पताः—1. तेजई पुत्र फेरन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी बसन्तापुर थाना खैरीघाट जनपद बहराइच मु0सं0 838/19 व अ0सं0 266/18 धारा 323,504,427,325,452 भादवि थाना खैरीघाट जनपद बहराइच से सम्बन्धित2. रामकुमार पुत्र मेवालाल उम्र करीब 42 वर्ष निवासी भयापुरवा दा० लौकिहा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच मु0सं0 14193/18 व अ0सं0 435/19 धारा 323,325,504,506 भादवि से सम्बन्धित3. रामरूप पुत्र लाल उम्र करीब 38 वर्ष निवासी भयापुरवा दा० लौकिहा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच मु0सं0 14193ध18 व अ0सं0 435/19 धारा 323,325,504,506 भादवि से सम्बन्धित4. जगदीश पुत्र छेद्द उम्र करीब 45 वर्ष निवासी लौकिहा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच मु0सं0 13806/18 व अ0सं0 17/09 धारा 323,504,506 भादवि थाना खैरीघाट जनपद बहराइच से सम्बन्धित5. लाल बहादुर पुत्र स्व० मिश्रीलाल निवासी मटेराकला थाना खैरीघाट जनपद बहराइच उम्र करीब 55 वर्ष मु0सं0 14634/19 व अ0सं02/19धारा323,325,504,506 भादवि थाना खैरीघाट जनपद बहराइच से सम्बन्धित 6. पृथ्वीराज पुत्र शंकर निवासी नेवादा पूरे कस्वाती थाना खैरीघाट जनपद बहराइच उम्र करीब 45 वर्ष मु0सं0 2103/2018 धारा 147/352/504/506 भादवि थाना खैरीघाट जनपद बहराइच से सम्बन्धितगिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण—1. उ0नि0 रामसुधार यादव (चौकी प्रभारी चौकी वैवाही)2. उ0नि0 रामप्रवेश यादव3. उ0नि0 लालधर प्रसाद4. उ0नि0 मारकण्डेय तिवारी5. उ0नि0 अजीत मौर्या6. हे0का0 मित्रपाल7. हे0का0 अजय कुमार8. का० अंकुर सिंह9. का0 विकास दुबे थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।

तहसीलों में आयोजित हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस

स्टेट ब्यूरो अब्दुल नासिर

बहराइच। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए तहसील महसी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र ने उप जिलाधिकारी आलोक प्रसाद, पुलिस क्षेत्राधिकारी डी.के. श्रीवास्तव व अन्य अधिकारियों के साथ आये हुए फरियादियों के समस्याओं की गम्भीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिये गये। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये कि पूरी संवेदनशीलता के साथ जनसमस्याओं का निस्तारण करते हुए गरीब व पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल न्याय दिलाया जाय। गरीब, जरूरतमन्द तथा असहाय लोगों की हर संभव मदद भी की जाय तथा उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाय। सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 69 आवेदन पत्रों में से 05 का मौके पर निस्तारण किया गया। सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सीडीओ द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोदभराई व बच्चों का अन्नप्रासन्न भी कराया गया।

उल्लेखनीय है कि तहसील नानपारा में अपर जिलाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 26 प्रार्थना—पत्रों में 07 का निस्तारण किया गया। इसी प्रकार तहसील पयागपुर में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त 14 में 05, तहसील सदर बहराइच में 10 में 02, कैसरगंज में 18 में 04 तथा मिहींपुरवा में 12 में 02 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संजय कुमार, डीडीओ राज कुमार, पीडी डीआरडीए मनीष कुमार, डीपीआरओ सी.बी. सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनोद राय, जिला पूर्ति अधिकारी नरेन्द्र तिवारी, जिला गन्ना अधिकारी आनन्द शुक्ला व अन्य अधिकारियों सहित बीडीओ, बीईओ, सीडीपीओ व थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

जनपद बहराइच थाना कोतवाली नानपारा मिशन शक्ति केंद्र के तहत पारिवारिक विवाद का निस्तारण

स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल नासिर

नानपारा। थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के मिशन शक्ति केंद्र पर गुरुवार को पारिवारिक विवाद संबंधी प्रकरण में काउंसलिंग कराई गई। मिली जानकारी के अनुसार, आवेदिका शाहिरा पत्नी शकील निवासी तकिया, थाना

नानपारा, जनपद बहराइच द्वारा पारिवारिक विवाद के संबंध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

मामले पर मिशन शक्ति टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों पक्षों को केंद्र पर तलब किया और काउंसलिंग कराई। काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को आपसी समझ और सहयोग से विवाद का समाधान निकालने की सलाह दी गई। मिशन शक्ति केंद्र का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करना है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं को न्याय दिलाने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

जनपद बहराइच प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह नानपारा के नेतृत्व में अगैया चौराहा पर पैदल गश्त थाना नानपारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत

स्टेट ब्यूरो अब्दुल नासिर

नानपारा। शहर में शांति एवं कानून—व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह नानपारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अगैया चौराहा क्षेत्र में पैदल गश्त की।

इस दौरान उप निरीक्षक सौरभ पांडे, कांस्टेबल अमित सिंह, कांस्टेबल अशोक यादव तथा कांस्टेबल विनय चौधरी मय फोर्स उपस्थित रहे।

गश्त के दौरान टीम ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की और लोगों से सतर्क रहने की अपील की।

प्रभारी निरीक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि गश्त का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण एवं आमजन में सुरक्षा का भाव बनाए रखना है।

धारा—24 के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु जनपद में संचालित होगा महा अभियान

डीएम अक्षय त्रिपाठी की अभिनव पहल

स्टेट ब्यूरो अब्दुल नासिर

बहराइच 16 अक्टूबर। बुधवार को देर शाम जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा जिले के समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल के साथ वर्चुअल बैठक कर धारा—24 के राजस्व वादों की गहन समीक्षा की गई। उल्लेखनीय है कि पूर्व में की गई बैठक में पक्की मेडबंदी के लंबित प्रकरण संकलित करने से ज्ञात हुआ कि विगत 03 वर्षो में धारा—24 के निस्तारित राजस्व वादो में कैसरगंज में 167, नानपारा में 202, पयागपुर 110, सदर में 96, महसी में 134, मिहींपुरवा 79 इस प्रकार जनपद में कुल 788 मामले पक्की मेड़बन्दी हेतु लम्बित है।

डीएम श्री त्रिपाठी द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल को निर्देशित किया गया की 15 अक्टूबर से खेतों की कटाई शुरू हो जाने से खेत खाली हो जायेंगे इसलिए इस स्थिति का लाभ उठाते हुए आगामी 1—2 महीनों में जनपद में लम्बित सभी (मेड़बन्दी) धारा—24 के राजस्व वादों का यथाशीघ्र अभियान संचालित कर निस्तारण कराया जाय। डीएम द्वारा सभी सम्बन्धित को यह भी निर्देश दिया गया कि धारा—24 के सभी वाद ऑनलाइन दर्ज कर लिए जाए तथा लम्बित वादो में समय से सभी सीमांकन आख्या प्राप्त कर राजस्व वादो का समयान्तर्गत निस्तारण कर मेड़बन्दी करा दी जाये ताकि अभियान के उपरान्त कोई भी मेड़बन्दी के प्रकरण लम्बित न रहें।

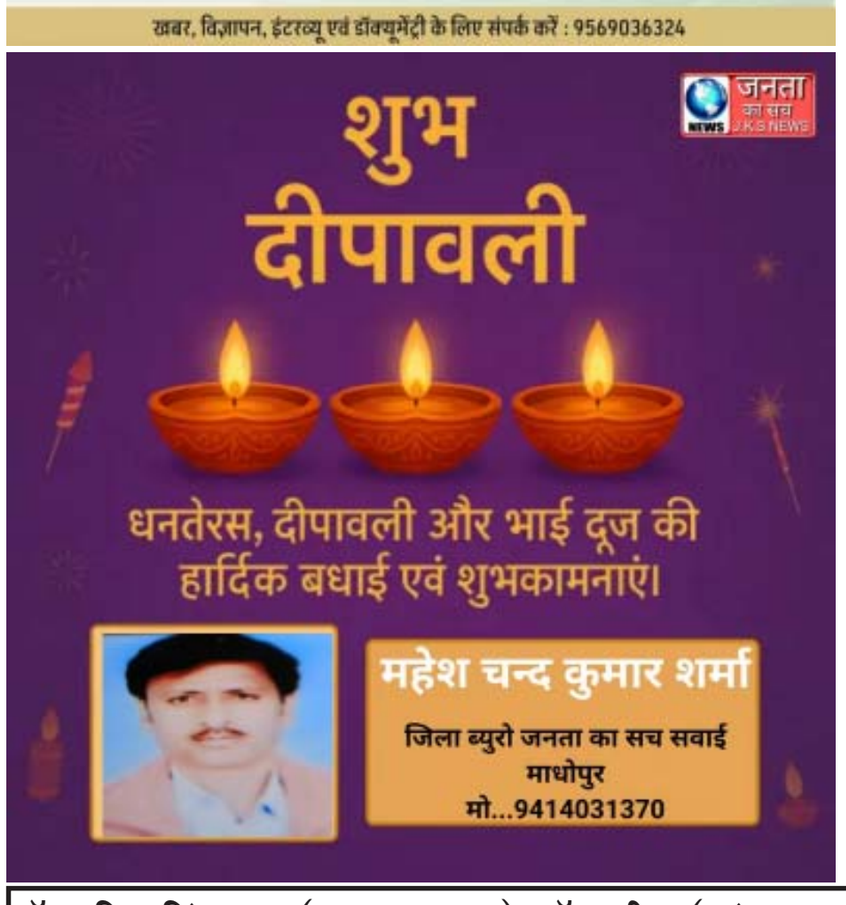

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।